(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

Revival of BPMEL

6457. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI MD. SALIM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2784 given in the Rajya Sabha on the 30th March, 1995 and state:

(a) the number of orders procured by M/s. Braithwaite after they were assigned the job of absorbing the full technology acquired through collaboration by BPMEL;

(b) whether in the second BIFR hearing held on 19th April, 1993, Government representative informed the Bench-III of BIFR that land/building occupied by BPMEL's factory are on lease from a jute mill under Ministry of Textiles and the Bench had directed Government to submit a comprehensive note regarding the legal status of the title of land/building occupied by BPMEL;

(c) whether, in pursuance of the above decision of the Bench, the Ministry of Industry had taken up the matter regarding transfer of land at Dakhindari with the Ministry of Textile;

(d) if so, at what point of time, BIFR or the operating agency was informed regarding 7 lakh sq. ft. of land at Dakhindari; and

(e) whether the fact that the legal possession of seven lakh sq. ft. is yet to be taken over and the market value of the same has not been assessed so far, amounts to concealment of material fact before BIFR?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Nil.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, sir.

(d) and (e) It has been reported by BPMEL that IDBI was informed about the status of 7 lakh sq. ft. of land when their representative visited company's head office and works after it was appointed DA on 19.4.93 by BIFR. Therefore there was no concealment of material fact.

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना

6458. श्री रामजी लाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों को रोजगार दिलाकर गांवों के विकास हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने वर्ष 1995-96 और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान कितने लोगों को रोजगार मिलेगा;

(घ) इस योजना के बाजवूद कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार रह जायेंगे; और

(ङ) बेरोजगार व्यक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) उद्योग, सेवा और व्यापार उद्यमों के जरिए 7 लाख माइक्रो उद्यम स्थापित करके 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 2.10.1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। वर्ष 1993-94 के दौरान यह योजना देश के केवल शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई। 1 अप्रैल, 1994 से यह योजना देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलाई जा रही है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान 31,797 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण मंजूर किए गये थे। नवीनतम उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान 1,87,625 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण मंजूर किए गये थे।

योजना की आवश्यकता के अनुसार वर्ष-वार धनराशि प्रदान की जाती है। 1993-94 और 1994-95 और 1995-96 के बजट प्रावधान में जारी की गई वर्ष-वार धनराशि नीचे दी गई है:—

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन जारी की गई धनराशि

क्र०सं०	वर्ष	भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत पूंजीगत राज सहायता (रु० करोड़ में)	प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और योजना का मूल्यांकन इत्यादि (रु० लाख में)
1.	1993-94	30.00	478.59
2.	1994-95	74.53	2052.51
3.	1995-96*	120.00	2500.00

*बजट प्रावधान—प्रस्तावित

(ग) से (ङ) योजना आयोग द्वारा दिये गये नवीनतम अनुमानों के अनुसार मार्च 1995 के अंत में देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगभग 187 लाख है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन चल रहा कोई एकक 2 व्यक्तियों को रोजगार देने की संभावना रखता है। इस योजना के तहत पहले 2 वर्षों में कार्यान्वयन में बैकलॉग सहित 1995-96 के दौरान 2.60 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

Industrial entrepreneur memorandum

6459. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proposed employment to be generated through the IEMs filed since the announcement of new economic policy is for about 32 lakhs persons;

(b) what is the number of IEMs commissioned and under implementation; and

(c) what is the actual investment by entrepreneurs under the implementation of the proposals and what is the number of person employed so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir. Since the announcement of New Industrial Policy till 31st December, 1994, 17064 Industrial Entrepreneur Memoranda (IEMs) with a proposed employment for 32,24,449 persons have been filed with Government for establishing new units/ new articles/expansions of existing industrial units etc.

(b) and (c) As on 31st December, 1994, commencement of commercial production in respect of 1425 IEMs with an investment of Rs. 48,576 crores have been reported to the Government of India by Entrepreneurs. Information on IEMs under implementation or employment created from implementation of IEMs are not centrally maintained.

Reasons for losses incurred by PSUs

6460. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have conducted a thorough probe into the facts and reasons of losses being incurred by some of the Public Sector Units which are becoming sick-day-by-day;

(b) whether it is a fact that sick Public Sector Units were never allowed to update their technological development due to want to capital investment nor were these PSUs ever given proper working capital to generate their own resources for developmental works;

(c) the names of PSUs under Ministry